of suspended animation for the past two-three days, is taken up, I will be better able to answer all these questions relating to IC-814 because they really arise with that satement, and not so much from this aprticular question itself. As the hon. Member has said, yes, we mentioned what the U.S. President had said as also what the spokesman had said. Here, I would like to say two things. We told our Mission to find out, to seek a clarification as to whether it was in response to an earlier question, and we were informed that until the United States of America goes through the completion of its own legal processes, they have some diffculties in making direct announcement of that kind. Nevertheless, the U.S. Secretary of State has said that they believed that the Harkat was involved in the hijacking of IC-814. As the hon. Members are, no doubt, aware that Harkat has intimate links with the ISI and the Government of Pakistan, as has been brought out in my statement on hijacking of IC-814.

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : सभापति महोदय, इतने प्रश्नों के जो उत्तर दिये गये, उसके बाद यह संदेह की स्थिति रहती है कि हमारी आंतरिक कमज़ोरियां क्या है जिनकी बदौलत आई0एस0आई0 या दूसरी टेररिस्ट आर्गेनाइज़ेशंस हमारे देश के अंदर इंफिल्ट्रेशन में सफल हो जाती है और हमको इतनी तबाही में डाल रही है। क्या सरकार ने उन कमज़ोरियों को रेखांकित किया है, यदि किया है तो उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये है खास तौर से कारगिल युद्ध के बाद?

श्री जसवन्त सिंह : सभापति जी, माननीय सदस्य ने आंतरिक कमज़ोरियों के बारे में प्रश्न पूछा है। सरकार निश्चित रूप से उनके प्रति सजग भी है और सचेत भी है और सभी कुछ कर रही है। मेरा निवेदन होगा जो सरकार कर रही है, उसी प्रकार माननीय सदस्य भी अंतर्मुखी हो कर देखें कि वह आंतरिक कमज़ोरियां क्या है जिनके कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है।

Famine Relief to Rajasthan

*102. SHRI AIMADUDDIN AHMAD KHAN (DURRU): Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) how much funds have been demanded by the Rajasthan Government for famine relief works during the current financial year i.e. 1999-2000 and how much funds have been released by the Government.

(b) how much additional funds will now be released by Government for this purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI HUKUMDEO NARAYAN YADAV): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The entire Central share of Calamity Relief Fund(CRF) for 1999-2000 amounting to Rs. 155.25 crore has been released to the State for undertaking immediate relief measures in the wake of natural calamities, including drought. The State Government's Memorandum seeking assistance of Rs. 1144.40 crore from the National Fund for Calamity Relief (NFCR) in the wake of drought is being dealt with in accordance with the established procedure. The National Calamity Relief Committee (NCRC) will consider the request of the State Government, take all relevant aspects into account and approve the quantum of assistance if any, from the NFCR, which will then, be released to the State Government.

SHRI AIMADUDDIN AHMAD KHAN (DURRU): Hon, Chairman, Sir, in 1998, Rajasthan faced famine conditions which affected 20,069 villages of twenty districts in which 2.15 crore people and 2.95 crore cattle were affected by this famine. Due to the crop failure, there was an acute shortage of fodder and drinking water. The State had to spend Rs. 465 crores to deal with the famine.

In 1999, again, the rainfall failed in Rajasthan. It was below the normal and it was erratic too. Firstly, due to the lase start of rains, the sowing of crops was badly affected. Only 66.5 per cent of the areas was sown, thereafter, due to shortfall in rains, 60 to 75% damage is estimated to the crops. The cost of the most common variety of fodder has gone up to Rs. 4 per Kg. in some districts. 23,406 villages, spread over 26 out of the 32 districts of the State have been affected. 2.61 crore people and 3.45 crore cattle have been affected by this famine. The State Government has already brought these far to the attention of the Central Government on 7th October *vide* a letter from the Relief Department of the State to the Agriculture Deaprtment, on 5th November from the Chief Secretary of Rajasthan to the Secretary, Department of Agriculture and on 2nd December, 1999,

from the hon. Chief Minister to the hon. Prime Minister.

A Central team visited the State from the 9th December to the 12th December and I presume that they have submitted their report shortly thereafter. Against the State Government's demand of Rs. 1,144.4 crores from the NSCR, the Central Government had released only a CRF amount of Rs. 155.25 crores, which would have been given even under normal circumstances. I wish to draw your attention....

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

SHRI AIMADUDDIN AHMAD KHAN (DURRU): I am just coming to that.

MR. CHAIRMAN: Start with that then.

SHRI AIMADUDDIN AHMAD KHAN (DURRU): I would like to draw your attention to a news report of the *Indian Express. (Interruptions)* My first supplementary'is, looking at the gravity of the situation, why has the NCRF meeting hot been convened yet?

श्री हुक्म्देव नारायण यादव : महोदय, जो राज्य सरकार से प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे उसके आधार पर केन्द्रीय टीम ने वहां सर्वेक्षण किया। उसके आधार पर केन्द्र की तरफ से जो निधि है उसके लिए बैठक शीघ्र ही बुलाने का प्रस्ताव है और करीब-करीब मार्च के अंदर ही वह बैठक बुलाकर हम निर्णय लेने वाले है।

SHRI VAYALAR RAVI: What does the survey report say?; Why can you not implement it? *(Interruptions)* Please look into what the survey report says. *(Interruptions}* You are discriminating against the Congress Government. That is the complaint. *(Interruptions)*

SHRI AIMADUDDIN AHMAD KHAN (DURRU):That is whay I was wanting to bring the gravity of the situation to your notice and to the notice of the House.

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is not for discussion.

SHRI AIMADUDDIN AHMAD KHAN (DURRU):For the last six months, we have had this famine and yet, for six months, the hon. Minister had not called a meeting of the Council. This is a very-very sharmeful fact.

The second supplementary that I would like to ask the hon.

Minister is, will the hon. Minister provide details of the released amount to other States where even after fully exhausing the CRF allocations, additional amounts from the Centre were released, without the NCRF meeting.

श्री हुक्म्देव नारायण यादव : सभापति महोदय, जहां तक राजस्थान सरकार का प्रतिवेदन है, वह मैंने पहले बताया कि हमारे पास उनकी जो मांग थी, जैसा माननीय सदस्य कह रहे है जो 207 करोड़ थी, उसमें 155 करोड़ रुपया भारत सरकार का 51 करोड़ रुपया राज्य सरकार को देना था, वह निधि अभी आपके पास है । तब तक उसको राज्य सरकार रिलीफ के काम में लगाए ।शेष जो आपने मांग की है, उसके आधार पर हम जल्दी ही बैठक करके और फैसला करके राशि विमुक्त करेंगे, जिससे आगे कार्यवाही होगी । अन्य राज्यों का जहां तक प्रश्न है, वह प्रश्न जब पूछा जाएगा तब सब को बता देंगे ।

श्री ऐमादुद्दीन अहमद खान (दुरू) : मैं तो आप ही से पूछना चाह रहा हूं कि जब और राज्यों में, जैसा आन्ध्र प्रदेश में आज से करीबन तीन साल पहले साइक्लोन आया था और बगैर मीटिंग किए हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने 200 करोड़ रुपया रिलीज़ कर दिया था, तो हमारे राजस्थान के लिए इनकी क्या परेशानी है कि एडहॉक, बगैर मीटिंग किए हुए कोई इस तरह का फंड रिलीज़ न किया जाए? क्या यह इस वजह से नही है कि वहां हमारी कांग्रेस की सरकार है और वहां आपकी एलाई की सरकार थी?

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदा के बारे में राजनीति की जा रही है, यह आरोप ठीक नही । केन्द्र सभी प्रदेशों को समान रूप से देखता है जहां पर स्थिति अधिक गंभीर है, वहां पर पहले मदद पहुंचाने का केन्द्र प्रयास करता है ।

डा0 अलादी पी0 राजकुमार : 200 करोड़ रुपये दिए थे और 200 करोड़ रुपये ले लिए थे । They have taken it back **...(व्यवधान)...**

In Andhra Pradesh it was a national calamity....*(Interruptions)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, प्रदेश एक-दूसरे पर आरोप न करें और केन्द्र भी कभी इन मामलों के बारे में भेदभाव से काम नही लेता । राज्यों को जहां धन दे दिया जाता है वहां यह देखा जाता है कि वह धन खर्च हो गया या नही अब मैं राज्य का नाम नही लेता, लेकिन केन्द्र से धन पहुंचा दिया गया है अभी तक वह खर्च नही हुआ है । उसकी सूचना केन्द्र को नही मिली है । इसलिए और धन देने में थोड़ा सा विलम्ब होता है, क्योंकि पहले दिया गया धन खर्च हो जाए, उसके बाद और धनराशि दी जाएगी । इसके कारण गलतफहमी नही पैदा होनी चाहिए ।

डा0 योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ : सभापति महोदय, राजस्थान के पास में जो

पश्चिमी गुजरात के जिले है, उनमें जो इस बार अकाल आया है, वह सब से बड़ा अकाल है । मैं गुजरात की एन0जी0ओज़ का चेयरमैन हूं और इंडिया वाटर पार्टनरशिप का भी चेयरमैन हूं उस अकाल को यह कहा जाता है कि वह इस सदी का सब से बड़ा अकाल है । इसलिए उन जिलों के बारें में भी क्या माननीय मंत्री जी हमको कुछ बतायेंगे, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अब उन जिलों का सर्वेक्षण कर रही है, इतनी गंभीर समस्या गुजरात में है ।

श्री हुक्म्देव नारायण यादव : महोदय, गंभीर समस्या तो है, लेकिन हमारे पास अभी जो प्रश्न जिन राज्यों के संबंध में पूछे गए हैं उन्हीं के उत्तर हैं और उसका ही जवाब देंगे । गुजरात वाला आपने नोटिस में लाया है तो उस पर भी हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे कि गुजरात को भी मदद कर सकें ।

डा0 योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ : महोदय, उसके साथ में जुड़े हुए जिले, जैसलमेर के पास के जो जिले हैं वहां बहुत बुरी तरह से अकाल आया है । मंत्री महोदय कुछ तो हमको गुजरात के बारे में बताएं कि क्या कह रहे हैं । अब प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो पॉलिटिक्स की बात कर ही नहीं रहा हूं और वैसे भी गुजरात में तो बी0जे0पी0 की सरकार है ।

श्री रामदास अग्रवाल : सभापति महोदय, राजस्थान में जो अकाल की विभीषिका है उसके संबंध में माननीय सांसद ने जो कहा है, मैं उससे सहमत हूं । इस समय वहां पर अकाल की बडी भीषण अवस्था है और कई महीनों से अकाल राहत के काम खोलने में राज्य सरकार विफल रही है । वह, सफलतापूर्वक वहां काम नही कर पा रही है और बार-बार सभापति महोदय, वह यह कह चुके है ऑन रेकार्ड, कि उनके पास किसी भी प्रकार से अकाल राहत काम खोलने के लिए पैसा उपलब्ध नहीं है, साधन उपलब्ध नहीं हैं ।

मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से उत्तर चाहूंगा कि आप ने प्रदेश को जो 155 करोड़ रुपया भेजा, क्या उस के उपयोग के संबंध में आप को राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गयी है? यह मेरे प्रश्न धन की बर्बादी के बारे में आज ही अखबारों में छपा है कि पशु धन की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है जिस कारण वहां से अन्य क्षेत्रों के लिए पशुओं का पलायन हो रहा है और लोगों में चिंता व्याप्त है, सभापति जी, वहां मनुष्यों के पीने के लिए जल नहीं हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है और सवाल राहत के काम भी नही हो रहे है । इस तरह राज्य सरकार अपना उत्तरदायित्व निभाने में विफल रही है । इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता को केवल राजस्थान की कांग्रेस सरकार की दयनीय स्थिति पर न छोड़ा जाय और इस स्थिति में केन्द्र सरकार जो कुछ कर सकती है, वह करने के लिए आगे आए । साथ ही जो कुछ धन आप के द्वारा दिया है, उस पर उपयोग वाकयी अकाल राहत के कामों में हुआ या नहीं, इस की जानकारी भी दें ।

श्री हुक्म्देव नारायण यादव : सभापति महोदय, राज्य सरकार को जो पैसा हम देते हैं, उस के संबंध में राज्य सरकार से हमें उपयोग प्रमाण-पत्र आते हैं जिस के आधार पर आगे कार्यवाही होती है लेकिन राज्य सरकार से इस संबंध में हमारे पास पूरे प्रमाण पत्र उपलब्ध हुए या नही हुए, अभी मैं इस बारे में पूरा विवरण नही दे सकता । महोदय, राज्य सरकार से आए प्रमाण पत्र के आधार पर आगे कार्यवाही होती है और जहां तक राजस्थान को सहायता देने का प्रश्न है, केन्द्र सरकार स्वयं चिंतित है कि राजस्थान को कैसे अधिक-से-अधिक पैसा दें, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी दें और उस पर आगे कार्यवाही हो । लेकिन राज्य सरकार उस राशि का उचित उपयोग करती है या नहीं करती है, वह राज्य सरकार पर निर्भर है और राज्य सरकार से इस की जानकारी ली जा सकती है ।

श्रीमती सरला महेश्वरी : माननीय सभापति महोदय, हालांकि प्रधान मंत्री जी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के संबंध में राज्यों के साथ कोई भेदभाव नही किया जाएगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे उल्टी है । राज्यों का अनुभव बिल्कुल इस के विपरीत है । जहां तक राजस्थान का सवाल है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या यह हकीकत नहीं है कि राजस्थान में आये इस भीषण अकाल के संबंध में केन्द्र सरकार ने बहुत ही ढ़ीला-ढ़ीला रुख अख्तियार किया है? इस बारे में मीटिंग तक नहीं बुलाई गई है और पैसा भी आज तक नहीं पहुंचाया गया है जबकि हमारे सदन के नेता स्वयं बाड़मेर जिले से आते है । वहां की स्थिति अत्यंत दयनीय है । शायद उन्होंने प्रधान मंत्री जी को वहां की स्थिति से अवगत कराया होगा ।

इस के साथ ही सभापति जी मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में पश्चिमी बंगाल का उदाहरण लाना चाहूंगी । पश्चिम बंगाल में भयंकर बाढ़ आई और प्रदेश के वित्त मंत्री जी ने पूरे डाटाज भेजे । सभापति जी, राज्य आपदा कोष से जितना करोड़ रुपया खर्चा किया गया, केन्द्र से उस के एवज में कुछ नहीं मिला । उन का कोष खत्म होने के बावजूद राज्य केंद्र की ओर से कोई राशि नही भेजी गयी । इस का क्या कारण है? क्यों आप इस तरह का ढ़ीला-ढ़ीला रुख अख्तियार करते हैं । माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल को बाढ़ राहत के लिए कितना रुपया दिया गया है?

श्री हुक्म्देव नारायण यादव : सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं आग्रह कर चुके हैं कि एक-दूसरे के प्रदेश के प्रश्न उठाकर यहां विवाद खड़े न किये जाएं, लेकिन राजस्थान के बारे में मैं माननीय सदस्या को जानकारी देना चाहूंगी कि दिनांक 15-11-99 को हमें राजस्थान सरकार की ओर से ज्ञापन प्राप्त हुआ, 25-11-99 को हम ने उन से स्पष्टीकरण की मांग की , 29-11-99 को उन का उत्तर प्राप्त हुआ । दिनांक 24-11-99 को केन्द्रीय दल का गठन हुआ और 10 जनवरी से 13 जनवरी तक केन्द्रीय टीम ने संपूर्ण राजस्थान का दौरा किया जिस की रिपोर्ट हमारे पास आ गयी है । अब आप बताइए कि कहां विलंब हो रहा है? नवंबर में हमारे

पास ज्ञापन आया और जनवरी तक हम निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर चुके है । अब आगे खर्च करने के लिए हम आप को पैसा देंगे तब तक आप 260 करोड़ रुपया खर्च करिए ।

श्रीमती सरला महेश्वरी : महोदय, यह क्या तरीका है? जरूरत के समय पैसा देंगे नही और आप सिर्फ हैलीकॉप्टर में घूम-घूमकर सर्वे करते रहेंगे । क्या प्राकृतिक विपदा से निपटने का तरीका है? ...(**व्यवधान**)...

डा0 योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ : मंत्री जी, इस बारे में आप की क्या स्टेडिंग है? THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI JASWANT SINGH): I appreciate the point raised by hon. Shri Alagh *...(Interruptions)....* I do appreciate. I am not speaking parochially. Natural calamities do not see any political distinction. As has been said by the hon. Prime Minister, while referring to the natural calamities, the political distinctions can simply not be maiantained because they are calamities that affects all human kind. The drought has affected Kutch, kathiawad, parts of Saurashtra, adjoining Jaisalmer and Barmer districts. I say this because my hometown is in Banner district.

I have direct knowledge, more than any other Member of this House, of what is taking place there. I do not wish to comment on what the Government of Rajasthan is doing, or not doing. But I do wish to assure you that the addressing the situation of Rajasthan and the adjoining districts of Gujarat, in totality, is very much in the Prime Minister's mind. They will receive due attention.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, it sounds very good when the Prime Minister says, "We should not politicise this matter." I fully agree with him. But unfortunately the experience in Orissa and Rajasthan has been that the Government itself is politicising these issues. I am not talking about Orissa, but in Rajasthan, if the need is for Rs. 1444 crores, and the Government give only 10 per cent, that is, about Rs. 150 crores, I cannot understand how the Rajasthan Government can function. Even in 1987-88, when the Congress Government was there, when the famine was of a much lesser kind, the Central Government gave about 700 crores of rupees. So, now we require, maybe, twice or thrice. In the month of December, the Prime Minister had been kind enough to declare that the Rajasthan famine is a national calamity. Mere declaration is not going to help.

Our hon. Minister has just now said that he has just received the report. They are studying it. Sir, six months — October, November, December, January, February and March —have already passed— Will the Government consider the matter now and not when there will be no people, no cattle — when there will be nobody to take the relief? I would like to give you an example: in Jodhpur, a family had 25 cows, but now they have only two cows. This is the situation there. What are you going to do to tackle this situation? Why can't you act more effectively, when the report is already with you? Can you give us a time frame for taking action? If you want to give the funds, please give it. If you do not want to give, declare it; and let the people of Rajasthan die.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि किसी तरह का विलम्ब नहीं किया गया है । केन्द्रीय आपदा राहत निधि के लिए जो नियम और प्रक्रिया निर्धारित हैं, उस नियम-प्रक्रिया के तहत जितनी शीघ्रता होनी चाहिए उसी के अनुसार हर काम कर रहे हैं । मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस मार्च महीने में ही हम आपदा राहत निधि की बैठक बुलाकर, निर्णय करके आगे राशि विमुक्त करने वाले हैं और आपको कर देंगे ।

MR. CHAIRMAN: Shri Govindram Miri.

श्री गोविन्दराम मिरी : सभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)...

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Sir, will the Government of India send a team to watch the situation in Rajasthan and Gujarat. Dr. Alagh said, "In Banaskantha 700 cows have died." Whatever he said, he is right. It had appeared in headlines of the Gujarat press also. Will the Government see to it, and send a team to both the States to study the situation on the spot? *(Interruptions)*

श्री गोविन्दराम मिरी : सभापति महोदय, प्रायः राज्य अपनी असफलता के लिए केन्द्र को दोषी ठहराने के आदी हैं । मैं जानना चाहता हूं, कई राज्यों से शिकायत मिली है ...

श्री सभापति : सवाल राजस्थान से हैं, कई राज्यों से नहीं है ।

श्री गोविन्दराम मिरी : राजस्थान से कह रहा हूं कि जो केन्द्र से सहायता दी जाती हैं, उस धन का सदुपयोग न करके, समय पर हिसाब नहीं देते हैं और उस धन को अन्य मदों पर डाइवर्ट कर देते हैं, तो क्या इसके लिए केन्द्र सरकार ने, सैंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्टैप लिया है, उन पर कार्रवाई करने के लिए और अकाल से राहत देने के लिए कोई स्थाई उपाय करने जा रही हैं?

श्री सभापति : यह तो जनरल क्वेश्चन है ।

श्री ओंकार सिंह लखावत : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वर्ष 1999-2000 के लिए राजस्थान का जो ऐन्युअल सी0आर0एफ0 था वह 207 करोड़ का था और सैंट्रल का शेयर 155.25 करोड़ का था । माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 1999-2000 का अपना पूरा शेयर, 155 करोड़, चार किश्तों के अंदर राज्य सरकार को दे दिया लेकिन मेरी जानकारी यह है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह तक एक भी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया – पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई, चारे की व्यवस्था नहीं हुई । कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ और शत-प्रतिशत राहत मिल गई । 1999-2000 का जो शेयर बनता था सैंट्रल गवर्नमेंट का उसकी । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कार्य प्रारम्भ होने की कोई सूचना हैं?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Tripartite Standing Labour Committee

*103. SHRI RAMDAS AGARWAL:

SHRI K.C. KONDAIAH:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have so far received any report from the Group of Ministers who were asked to look into wage revision as well as other labour related demands of various unions of Public Sector Undertakings;

(b) whether 36th Session of the Tripartite Standing Labour Committee which was held, recently, in New Delhi took any note of the above demands of Labour Unions; and

(c) if so, what are the demands of the workers and by when Government's decision in this regard is likely to be announced?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) The Group of Ministers (GoM) constituted to look into wage revision and other labour related demands of various unions of Public Sector Undertakings (PSUs) was constituted only on 9-2-2000. The report of the GoM is yet to be received.